

11.29 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) TRANSFER OF HIGH COURT JUDGES
BACK TO THEIR STATES

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, आपात स्थिति के दौरान उस कालिमा अवधि में जब लोग जेलों में बन्द कर दिये गये थे, जेलों में भारी असुविधाएं थीं और इस के बारे में बहुत जगहों पर उच्च न्यायालयों में याचिकाएं भी दायर की गई थीं। जबलपुर के उच्च न्यायालय में मैं ने भी एक याचिका दायर की थी जो अंगतः स्वीकार की गयी थी। हैबियस कार्पस को भी बहुत सी याचिकाएं उच्च न्यायालयों में दाखिल की गई थीं। आठ हाई कोर्ट्स ने यह निर्णय दिया था कि उनके बारे में मुनवाई हो सकती है। बदला लेने की भावना से श्रीमती इंदिरा गांधी ने और खलनायक गोखले जी ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधियों का स्थानांतरण किया था। जब जनता सरकार शासन में आई तब विभिन्न अवसरों पर घोषणायें की गईं कि जिन न्यायाधियों को इस तरह से स्थानांतरित किया गया है उनको यह मौका दिया जाएगा कि वे चुनें कि वे अपनी जगहों पर वापिस जाना चाहते हैं अथवा नहीं। यह प्रश्न कई बार उठाया गया है। 5-4-77 को विधि मंत्री ने क्वेश्चन आवर में उत्तर दिया था कि सब जजों को यह स्वतंत्रता और मौका हम देना चाहते हैं। फिर 13 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात को दोहराया था। इसके बाद 14 जून को श्री चन्द्र ने जो कि विधि मंत्री के स्थान पर उत्तर दे रहे थे कहा था :

7 Judges have requested for transfer

भेरा निवेदन है और आप से कहना है कि बहुत से न्यायाधिसि हैं जिन से

पूछा तक नहीं गया है कि वे वापिस जाना चाहते हैं अथवा नहीं। जबलपुर के उच्च-न्यायालय में आंध्र प्रदेश से आए कुड्डेया साहब से पूछा नहीं गया है। इसके कारण सीनियरिटी के मामले भी कुछ उलझे हुए हैं। निकट भविष्य में कुछ पदोन्नतियों होनी हैं और उन में भी क्वाइट पैदा होने की सम्भावना है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जबलपुर उच्च न्यायालय के श्री आनन्द प्रकाश जी सैन ने पैसला दिया था सरकार के खिलाफ और उनको भी बदले की भावना से स्थानांतरित कर दिया गया था। कुड्डेया साहब से पूछा नहीं गया है। सैन साहब की इच्छा है कि वे जबलपुर जाएं। लेकिन उनसे पूछा नहीं गया है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में शीघ्रता बरती जाए। 28 नून को विष्णु स्पाट रूप से यह घोषणा की गई थी कि उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों से जिन का स्थानांतरण किया गया था पूछा जाएगा कि वे वापिस जाना चाहते हैं अथवा नहीं। मेरी विधि मंत्री जी ने आपके तथा सदन के माध्यम से प्रार्थना है कि वह इसके बारे में त्वरित कार्रवाई करें और उन से पूछा जाए कि वे वापिस जाना चाहते हैं अथवा नहीं और जाना चाहते हैं तो उनका वापिस भेजने की व्यवस्था करें।

(ii) DECISION OF THE GOVERNMENT TO SPLIT
FERTILISER CORPORATION OF INDIA

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Mr. Speaker, Sir, I would like to raise an important issue. An announcement was made by the hon. Minister, Shri Bahuguna, for creating four units by splitting the FCI. This Corporation consists of several fertiliser companies and a sum of Rs. 700 crores have been invested into them. Some of them are not functioning and some of them are running into losses. So, effective steps are necessary for making these units viable. But instead of taking into consideration that aspect, Shri Bahuguna, hon. Minister of Chemicals and Fertilisers has come to the conclusion to split it. What will be the impact on